भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *45

गुरुवार, 28 नवम्बर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक)

शहरी बेरोजगारी

***45. श्री देरेक ओब्राईन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार, तीन युवाओं में से एक युवा न तो शिक्षित है, न नियोजित है और न ही प्रशिक्षित है तथा इस समूह में 95 प्रतिशत महिलाएं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि शहरी बेरोजगारी दर 14.7 प्रतिशत है और महिलाओं के संदर्भ में यह बेरोजगारी दर 20.1 प्रतिशत है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार शहरी बेरोजगारी संबंधी कोई कार्यक्रम शुरू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मंडाविया)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"शहरी बेरोजगारी" के संबंध में श्री देरेक ओब्राईन द्वारा दिनांक 28-11-2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *45 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) भारत में रोजगार/बेरोजगारी संकेतकों का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15-29 वर्षीय युवाओं की सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2 % रह गई है जो युवाओं की वैश्विक बेरोजगारी दर 13.3% से कम है [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकाशित विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान, 2024 के अनुसार]।

इसके अलावा, आईएलओ- आईएचडी (मानव विकास संस्थान) द्वारा प्रस्तुत इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार, कुल युवा आबादी में बेरोजगार युवाओं का हिस्सा 2019 में 7% से घटकर 2022 में 5% हो गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2022 के दौरान कुल युवा आबादी (15-29 वर्ष) में से 37% युवा नौकरीशुदा थे, 35% युवा छात्र थे, 22% युवा पारिवारिक कार्य कर रहे थे और केवल 5% युवा बेरोजगार थे।

(ख) और (ग): पीएलएफएस डेटा के अनुसार, देश में शहरी क्षेत्रों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 7.7% से घटकर 2023-24 में 5.1% हो गई है। इसके अलावा, भारत में महिलाओं की रोजगार संबंधी स्थिति के संबंध में, पीएलएफएस के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 18.2% से बढ़कर 2023-24 में 26.0% हो गया है और शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर 2017-18 में 10.8% से घटकर 2023-24 में 7.1% हो गई है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। इन रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घोषित की गई रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप प्रदान करना, नियोजनीयता में वृद्धि करना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

***